@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

एकात्म भारत

इदं राष्ट्राय इदं न मम्

28-4-2020
वैशाख शुक्ल पक्ष, पंचमी,
मंगलवार, विक्रम संवत् 2077

इंदौर, e-paper : www.ekatmabharat.com

अब मदरसों में भी महामारी...

कानपुर और सहारनपुर के मदरसों के छात्र निकले कोरोना पॉजीटिव, तबलिगीयों ने दी थी तालीम

कानपुर, सहारनपुर व संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश के कानपुर में अचानक से कन्ना पॉजीटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे यहां के तीन मदरसों को बताया जा रहा है। कानपुर के हॉटस्पॉट में स्थित इन मगरसों के चालीस छात्र कोरोना पॉजॉटिव मिले हैं। इसके अलावा सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम मदरसे के एक छात्र ने संत कबीर नगर स्थित अपने परिवार के 19 सदस्यों को कोरोना वायरस दिया है। खास बात ये है कि इन छात्रों को कोरोना का संक्रमण देने के पीछे भी तबलीगी हैं। क्योंकि मरकज से निकले जमातियों ने इन बच्चों को पढ़ाया था और इनके साथ भोजन भी किया था।

कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। इसके चलते शहर में हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कोरोना संक्रमित मामलों में सबसे अधिक वो छात्र हैं, जो तालीम हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों से मदरसों में आए थे। शहर में अब तक 3 मदरसों से 56 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इन छात्रों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है। संक्रमित छात्र बिहार, झारखंड व कोलकाता के रहने वाले हैंये मदरसे हैं कानपुर के नौबस्ता का हिदायतुल्लाह मदरसा, जाजमऊ के अशरफाबाद मदरसा, कुलीबाजार और कर्नलगंज मदरसा। सभी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें कॉरंटाइन किया गया है। इनमें कुली बाजार के मदरसे में 42 मदरसा छात्रा कोराना पॉजिटिव तो नौबस्ता के मछरिया इलाके में स्थित मदरसे से बिहार के रहने वाले 8 छात्र पॉजिटिव हैं । जाजमऊ में स्थित मदरसे से 6 छात्र पॉजिटिव निकले हैं।

जमातियों के संपर्क में हुए पॉजिटिव

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद जमाती शहर की विभिन्न मस्जिदों और मदरसों में ठहरे थे। ये जमाती इन मदरसों में दीनी तालीम देने के लिए जाते थे। मरकज के जमातियों के संक्रमित होने के बाद कानपुर में भी जमाती पॉजीटिव पाए गए। जिसके बाद उनके सम्पर्क मे रहने वाले लोगों की जांच की गई थी। जिलाधिकारी ब्रम्हदेव राम तिवारी का कहना है कि इन मदरसों के सभी छात्र क्वारेंटाइन हैं और इनका इलाज किया जा रहा है। अभी भी मदरसों से छात्रों के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।

देवबंद दारुल उलूम के 9 छात्र पॉजिटिव

सहारनपुर से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद के भी नौ छात्र कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है क्योंकि इस मदरसे में सैंकड़ों छात्र अध्ययन करते हैं। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 166 तक पहुंच गयी है। यहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही अब भी सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।

देवबंद दारुल उलूम के 9 छात्र में से आठ छात्र अफगानिस्तान के हैं तो वहीं एक छात्र रामपुर स्टेट का बताया गया है। देवबंद नगर की अगर हम बात करें तो देवबंद में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81 हो गई है। हालांकि सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा देवबंद नगर व गंगोह को पहले ही पूरी तरह से सील किया जा चुका है। वही दारुल उलूम देवबंद के जिन छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जांच करने के बाद पता लगा कि यह छात्र पहले से ही क्वॉरेंटीन किये जा चुके हैं। ये सभी देवबंद नगर के जामिया तिब्बिया, मदनी हॉस्पिटल सहित अन्य जगहों पर क्वॉरेंटीन हैं।

इस मामले में उपजिलाधिकारी देवबंद देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अब स्वास्थ्य विभाग दारुल उलूम के अन्य छात्रों की भी जांच करवाने की तैयारी कर रहा है।

देवबंद से लौटे छात्र के 19 परिजन पॉजिटिव

प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में देवबंद से लौटे एक छात्र के परिवार के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित छात्र असदुल्ला के परिवार के 29 सदस्यों के नमूने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। यह परिवार जिले के मगहर में रहता है। शुक्रवार की आधी रात के बाद आई जांच रिपोर्ट में 19 सदस्य संक्रमित पाए गए। इस सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग ने मगहर में डेरा डाला है। पूरे नगर पंचायत मगहर क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। डीएम ने कहा है कि सभी संक्रमितों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है।

इतने मामले सामने आने के बाद अब इस क्षेत्र में लोगों में घबराहट हैं। इसे देखते हुए अब यहां पर सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

प्रयाग में सेवा भारती बांट रही सवा लाख गमछे

प्रयागराज.

कोरोना से लड़ने के लिए मास्क या गमछा अनिवार्य होने के चलते सेवा भारती प्रयागराज और कौशांबी के लगभग सवा लाख ऐसे लोगों को गमछा देगी, जो कि मास्क का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। लॉक डाउन के चलते सेवा भारती पहले से ही खाद्य सामग्री का वितरण कर रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया था कि जो लोग मास्क नहीं ले सकते हैं। वे कोरोना से बचने के लिए कम से कम गमछे का उपयोग कर सकते हैं।

यह जानकारी सिविल लाइंस स्थित ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए दी। सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि अब तक प्रयागराज में 38 हजार परिवार को खाद्य सामग्री के पैकेट दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग ढाई लाख लोगों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए हैं। सेवा भारती ने प्रयागराज और कौशांबी में लगभग सवा लाख वंचितों की सूची तैयार की है जिन्हें राशन सामग्री के पैकेट के साथ ही गमछा भी दिया जाएगा। गमछा अंबेडकर नगर के जलालपुर स्थित फैक्ट्री से मंगाए जा रहे हैं।

पहली खेप में 20 हजार गमछे आ चुके हैं जिन्हें जिसे गुरुवार को वितरित किया जाएगा। बताया कि प्रयागराज विभाग में इस सेवा कार्य की केंद्रीय व्यवस्था सिविल लाइंस स्थित ज्वाला देवी विद्या मंदिर से संचालित हो रही है। महानगर में 29, गंगापार व यमुनापार में आठ-आठ केंद्र स्थापित किए गए हैं। संघ के विभाग प्रचारक कृष्णचंद्र, प्रांत सेवा प्रमुख सत्य विजय, अरविंद, भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी, सुबोध सिंह, पार्षद पवन श्रीवास्तव मौजूद रहे।

स्वदेशी स्वीकार-चीनी बहिष्कार स्वदेशी से बनाएं समृद्ध भारत

प्रोफेसर भगवती प्रकाश

भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है और इतनी ही अर्थात विश्व की 18.4% जनसंख्या चीन में भी है। लेकिन, विश्व के विनिर्माणी उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मैनुफेक्चरिंग में चीन का अंश 21.5% है, वहीं हमारा अंश मात्र 3% है। भारत में हम अपनी आवश्यकता व उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में जितनी अधिक भागीदारी स्वदेशी वस्तुओं की बढ़ाएंगे, उतने ही अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर हम, देश के सकल घरेलू उत्पाद भी उसी अनुपात में वृद्धि कर सकेंगे। ऐसी उत्पादन वृद्धि से ही सरकार के राजस्व की आय में वृद्धि होगी, व्यापार घाटे पर नियन्त्रण हो सकेगा और उससे रुपया भी सुदृढ़ होगा और इसके परिणामस्वरूप देश में उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो सकेगा। देश के बाजारों में आज चीनी वस्तुओं की भरमार से, जहाँ देश के बहुतांश उद्योगों के बन्द होने से हमें बेरोजगारी व बैंकों को नॉन परफार्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ रहा है। देश का विदेश व्यापार घाटा भी असहनीय हो रहा है।

पिछले वर्ष भारत का चीन के साथ 54 अरब डॉलर का विदेश व्यापार घाटा था एवं वर्ष 2017-2018 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 63 अरब (4.5 लाख करोड़ रुपये) का रहा है। भारत लगभग 90 अरब डॉलर (7 लाख करोड़ रुपये) का आयात करता रहा है। इस प्रकार भारत के साथ शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन का 7-10 लाख करोड़ रुपयों से आर्थिक सशक्तिकरण करना एक गम्भीर आत्मघाती कदम है।

चीन में 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के समय से ही चीन की साम्यवादी सरकार भारत के विरूद्ध निरंतर शत्रुतापर्ण कार्रवाईयों लिप्त रही है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके लगभग पूरे स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल (41,000 वर्ग किमी.) जितने 38,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल के अक्साई-चिन पर अधिकार कर लिया था, जो आज तक उसी के अधिकार में है। इसके साथ ही विगत 10 वर्षों से वह प्रतिवर्ष 150 से 400 बार हमारी सीमा में घुसपैठ करता रहा है और इन्हीं घुसपैठों के माध्यम से इंच दर इंच आगे बढ़ते हुए हमारे कई अत्यंत उर्वरा चरागाह क्षेत्रों व ऊंचाई वाले रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ हुये भारत के 1965, 1971 और 1999 के खुले युद्ध में भी चीन पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है। चीन की ये भारत विरोधी कार्यवाहियों बढ़ती ही जा रही हैं. हाल ही में चीन ने जून 2017 में सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसकर बुलडोजर से सेना के दो बंकर भी तोड़ दिए. इसी प्रकार चीन द्वारा इन विगत 10 वर्षों में अनेक अवसरों पर भारत द्वारा आतंकवादियों के सम्बन्ध में लाए प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र में विरोध, आणविक आपूर्ति समूह में प्रवेश का विरोध, ब्रह्मपुत्र का जल रोकना व आए दिन की घुसपैठ आदि सभी भारत के विरूद्ध घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां है। वस्तुतः चीन में 1949 में साम्यवादी सरकार के बनने के बाद से ही भारत के प्रति वह निरन्तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है. आज वह भारत के विरूद्ध आर्थिक, सामरिक, आतंकवादी व कूटनीति प्रेरक द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त हो प्रत्यक्ष व परोक्ष में सब प्रकार से हानि पहुंचाने के कार्य कर रहा है। स्वयं चीन की भारत विरोधी गतिविधियाँ तो चरम पर हैं ही, वह पाकिस्तान को भी हर प्रकार की भारत विरोधी कार्यवाही के लिए सभी वैध व अवैध तरीकों से सहयोग कर रहा है। देश में साधारण केल्कुलेटर, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी सेट जैसे उपभोक्ता उत्पादों से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज और सौर पैनल तक अनेक साज सामान चीन से आ रहे हैं। देश की कुल मांग का लगभग 50 से 90% तक चीन पर निर्भरता उचित नहीं है। यदि देश के सभी नागरिक चीनी वस्तुओं और अन्य भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए जहाँ -जहां भी स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध होने पर केवल स्वदेशी अर्थात मेड बाई भारत वस्तुओं व सेवाओं को ही क्रय करेंगे तो भारत विश्व की एक अग्र – पंक्ति की आर्थिक शक्ति बन सकता है। कृषि उद्योग व्यापार, वाणिज्य व विविध सेवाओं के क्षेत्र में हम क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। वर्तमान कोरोना जनित महामारी के कारण भारत सहित विश्व के सभी देश चीन से दूरी बनाकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार व चीनी वस्तुओं के आयातों और चीनी विदेशी निवेश पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध आरोपित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान कोरोना संकट व लॉकडाउन के बाद रिवर्स ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण के प्रतिगमन की प्रक्रिया आरम्भ होगी। भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में भारत चीन से आयातों पर निर्भरता न्यूनतम कर, दो अंको में आर्थिक वृद्धि दर अर्जित कर सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की जो विश्वसनीयता, सामर्थ्य व क्षमताएँ प्रकट हुई है, उसे देखते हुए भारत प्रत्यनपूर्वक विश्व का प्रमुख उत्पादन केन्द्र या मेन्युफेक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकेगा। इसके लिए हमे सर्वप्रथम चीनी व अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी होगी। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार और उससे चीन के पराभव से ही भारत के लिए उत्पादन, व्यापार व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (ग्लोबल सप्लाई चैन) का केंद्र बनना आसान होगा। आज हमारे चीन से

इलेक्ट्रानिक सामानों का आयात लगभग 45% है, मशीनरी आयात 35%, कार्बनिक रसायन 40%, मोटर वाहन स्पेअर्स और उर्वरक 25%, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री 65 – 70% और मोबाइल के साज सामान 90% व सोलर पेनल भी 90% चीन से आते हैं। भारत को विविध उत्पादों की आपूर्ति में चीन पर निर्भरता समाप्त करनी होगी। हमारे निर्यातों का 5% चीन को जाता है। चीन सामान्यतः कच्चे माल का आयात कर निर्मित वस्तुएँ हमे निर्यात करता है। हमें देश में उत्पादन को बढ़ावा देकर स्वयं ही अब कच्चे माल का उपयोग स्वयं ही करना चहिये। चीन जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पाद, रबर, कपास, अयस्कों आदि का ही प्रमुखता से आयात करता है। कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियार से विश्व मानवता के लिये उत्पन्न किये संकट के कारण सम्पूर्ण विश्व ही चीन से दूरी बनाता जा रहा है। इसलिए विश्व बाजारों में उसकी पहुंच समाप्ति की दशा में अब उसकी कच्चे माल की आवश्यकता भी न्यून या समाप्त हो जाएगी। चीन ने षड्यंत्र पूर्वक कोरोना वायरस से भारत सहित विश्व के विरूद्ध एक घृणित जैव आक्रमण किया है। उसे देखते हुए चीन की सभी वस्तुओं का बहिष्कार आज की प्रथम आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्व की व्यवस्थाओं को चौपट कर विश्व की एकमेव सत्ता बनने का दुःस्वप्न संजोकर चीन ने विश्व पर यह वायरस का आक्रमण किया है। ऐसे में वह विश्व को पंगु बना स्वयं एक मात्र महाशक्ति बन पूरे विश्व का अनादि काल तक शोषण करने में सफल नहीं हो जाये। इसके लिए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार सबसे सरल व सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। ऐसे में यदि हम टूथ पेस्ट, शीतल पेय, जूते के पॉलिश, बल्ब, ट्यूब लाइट, टीबी-फ्रिज, स्कूटर-कार, मोबाइल फोन, केल्कुलेटर व कम्प्यूटर सहित स्कूटर मोटर साइकल व कार पर्यन्त अधिकांश वस्तुओं में स्वदेशी ब्राण्ड या मेड बाई भारत अर्थात स्वदेशी वस्तुएँ ही क्रय करेंगे तो भारत शीघ्र ही विश्व का प्रमुख उत्पादन केन्द्र व अग्रणी आर्थिक शक्ति का स्थान ले सकता है। हमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी व विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में असेम्बल किये जा रहे उत्पादों के स्थान पर मेड बाई भारत या मेड बाई इण्डिया अर्थात पूर्ण स्वदेशी उत्पादों को ही क्रय करना चाहिए। "इस सम्बन्ध में स्वदेशी स्वीकार से हमारा आशय निम्नानुसार होना चाहिये"।

- स्वदेशी, अर्थात् भारतीय उत्पाद या मेड बाई भारत उत्पाद, सेवाएँ व ब्राण्ड ही खरीदना। विदेशी आयातित व विदेशी कम्पनियों के मेड इन इण्डिया उत्पादों को छोड़ देना। चीन में आयातित व चीन के मेड इन इण्डिया ब्राण्ड उत्पाद कतई नहीं खरीदना। चीन मेक इन इण्डिया करने हेतु जो विदेशी निवेश ला रहा है, उसे पैर जमाने का अवसर नहीं देना।

– आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या आर्थिक राष्ट्रवाद, तकनीकी राष्ट्रवाद और मेड बाई भारत की रीति-नीति (स्ट्रेटेजी) का प्रसार व संवर्द्धन

– कृषि व उद्योगों में यथेष्ट निवेश बढ़ाना

– देश की कृषि जैव सम्पदा अर्थात् हमारे बीजों व पशु 'नस्लों' का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण

– परिवार में सौहार्दपूर्वक सामाजिक समरसता के प्रसार के साथ हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के संरक्षण के साथ-साथ वेशभूषा, आहार व जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना इस दृष्टि से परिवारों में सकारात्मक व सम्पूरक संवाद व हिन्दी व अपनी मातृभाषा को बढ़ावा अपने पारम्परिक जीवन मूल्यों के दृढ़ीकरण और प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता का आत्मगौरव बढ़ाना भी आवश्यक है। इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, तकनीकी राष्ट्रवाद, मेड बाई भारत को प्रोत्साहन के साथ ही समग्र संस्कृति का संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है।

– कुटीर उद्योग, पारम्परिक कलाओं, पारम्परिक खाद्य, गीत, संगीत नृत्य नाटिकाओं का संरक्षण संवर्द्धन

अतएव विकास के लिये स्वदेशी उत्पाद व सेवाएँ अर्थात 'मेड बाई भारत' या 'मेड बाई इण्डिया' को छोड़कर कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। हम सभी देश भक्त हैं। देश के लिये आवश्यक है कि हम अपनी खरीददारी में रोजगार प्रधान स्थानीय उद्योगों व लघु उद्योगों की वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करें। विकेन्द्रित उत्पादन से ही समावेशी विकास सम्भव है। लघु उद्योगों के उत्पाद व ब्राण्ड उपलब्ध नहीं होने पर ही रोजगार विस्थापक बड़े उद्योगों के उत्पाद खरीदें। स्वदेशी उत्पादों की तुलना में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एवं विदेशों से आयातित उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करें। यदि विदेशी कम्पनियों के उत्पाद देश में नहीं बिकेंगे तो वे कुछ माह भी यहाँ नहीं टिक पाएंगी। स्वदेशी भाव जागरण से ही देश में स्वदेशी एक सशक्त मुद्दा बनेगा. स्वदेशी जागरण मंच 1991 से देश में वैश्वीकरण की शुरूआत के समय से ही यह आवाहन करता रहा है एवं इस मुद्दे पर जन जागरण करता रहा है। हम सब स्वदेशी जागरण मंच का ही अंग हैं। आइये हम सब स्वदेशी भाव जगाकर स्वावलम्बी राष्ट्र बनाएं। यदि अमेरिका जैसा देश (Be American-Buy American) का उद्घोष लगाता है तो हम स्वदेशी की बात क्यों नहीं करें। यदि एक सैनिक देश की राजनीतिक सम्प्रभुता के संरक्षण के लिए सीमा पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, तब हम भी देश की आर्थिक सम्प्रभुता के लिये आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा व्यक्त करते हुए विदेशी वस्तुओं को त्यागकर मेड बाई इण्डिया को बढ़ावा दें। ऐसा करके ही हम स्वयं व हमारी भावी पीढ़ी को आसन्न आर्थिक अराजकता से बचा पाएंगे। आइये, हम सब स्वदेशी जागरण मंच के मेड बाई इण्डिया अभियान को सफल बनाएं। स्वदेशी वस्तु, सेवाएं भाषा, भूषा, भोजन, पारिवारिक मूल्य, समरसता की परम्परा, हमारी जैव विविधता, कृषि, पशुधन, पारम्परिक कलाएँ आदि प्रत्येक स्वदेशी आयाम का प्राणपण से बल दें। इसके साथ ही विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें और चीनी वस्तुओं को तो भूल कर भी क्रय नहीं करें।

(वीएसके भारत से साभार)

दिल्ली हिंसा में जामिया एलुमनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष गिरफ्तार

शिफा-उर-रहमान जामिया समन्वय समिति का सदस्य है, कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सऐप से पुलिस के मिले प्रमाण

दिल्ली.

दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शन के समय हुई हिंसा में जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी है। उसका नाम शिफा-उर-रहमान बको दिल्ली दंगे में संदिग्ध भूमिका के कारण यूएपीए के बताया गया है। वह जामिया समन्वय समिति का सदस्यों भी है। पुलिस ने शिफा-उर-रहमान को यूएपीए (Unlawful Activities (Prevention) Act) यानि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अनुसार उनके पास कई तकनीकी साक्ष्य हैं जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हमारे पास उनके खिलाफ तकनीकी सबूत थे जो बताते हैं कि उन्होंने दंगों के दौरान भीड़ को उकसाया था। पुलिस के अनुसार वह सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था जो दंगा प्रभावित क्षेत्रों से एकत्र किया गया था। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार इसके बाद पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सऐप को भी चेक किया। जिसके बाद पुलिस को कई

महत्वपूर्ण प्रमाण हाथ लगे हैं। इन से यह बात पुख्ता हो गई है कि दिल्ली दंगे में उसकी भूमिका रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया। इसके बाद उसे 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी हाल के दिनों में 10 लोगों को दिल्ली दंगे के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर और सफूरा जगर को भी साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। जगर जामिया समन्वय समिति के मीडिया समन्वयक हैं वहीं, हैदर समिति का सदस्य हैं।

दिल्ली दंगे में कई लोगों की मौत हो चुकी थी वहीं, कई लोगों के घर-दुकान जल गए थे। पुलिस के एफआइआर में यह दावा किया गया है कि सांप्रदायिक हिंसा एक "पूर्व-निर्धारित साजिश" थी जो कि कथित तौर पर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और दो अन्य लोगों द्वारा रची गई थी। बता दें कि दिल्ली में हिंसा नागरिकता कानून के विरोध और समर्थकों के द्वारा भिड़ने के बाद शुरू हुआ था। यह 24 फरवरी को फिर दिल्ली में दंगे का रूप ले चुकी थी जिसमें करीब 53 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

कोरोना के चलते दाने-दाने को तरस रहे हैं पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी

अब तक न नागरिकता मिली और न राशन मिल रहा है, फिर भी खुश हैं कि भारत आ गए हैं, राजस्थान सरकार से नहीं मिल रही मदद

जैसलमेर.

भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को भी एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इसकी वजह से भारत के अलग-अलग कोनों में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान से भारत आए वे हिन्दू जिन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। वे नागरिक न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके चलते उनकी हालत और भी खराब हो गई है। वहीं राजस्थान सरकार इन्हें मदद दिए जाने का दावा कर रही है लेकिन वास्तविक हाल बहुत अलग हैं।

ऐसा ही मामला पाकिस्तान के सींदड़ा से दिसंबर 2014 में भारत आए 40 वर्षीय लिमू भील और उनका परिवार का हैं। हालांकि उन्हें कोरोना की परेशानी की जानकारी है और वे कहते हैं, "पूरा देश ही समस्याएं झेल रहा है लेकिन हम थोड़ा ज्यादा परेशान हैं। देश के नागरिकों के पास तो राशन कार्ड हैं, हमारे पास वो भी नहीं हैं। सरकारी जमीन पर रहते हैं। सरकार की किसी भी योजना में हमें कुछ नहीं मिलता है।" लीमू के परिवार को अभी भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, इसलिए ये सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। लिमू भील के तीन बेटे हैं और तीन बेटियां हैं। उन्हें और पत्नी को मिलाकर घर में कुल 8 सदस्य हैं और इस समय में उनके लिये अपने परिवार का भरण पोषण करना एक विषम समस्या बना हुआ है। पहले वह सिलाई का काम करके दिन के 200 रूपए तक कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम मिलना बंद हो चुका है।

जैसलमेर सिटी के पास ही सरकारी सेटलमेंट में रह रहे लिमू कहते हैं, "सरकार ने दिया था लेकिन संस्थानों ने दिया या नहीं, ये मालूम नहीं। महीने में पहली बार चावल और गेहूं परसों (22 अप्रैल) को ही मिला है। "लिमू भील अपने 5 भाई, बहन, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता समेत 30 सदस्यों के साथ पाकिस्तान से आ गए थे। अब सभी जैसलमेर में आसपास ही रहते हैं, किसी को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है और लॉकडाउन सभी परेशानी से जूझ रहे हैं।

भाग्यशाली हैं कि भारत आ गए हैं

वह बेहद खुशी के साथ कहते हैं कि हम तो रूखी सूखी रोटी खाकर गुजार लेंगे, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है।

लिमू की ही तरह साल 2004 में पाकिस्तान से आए प्रेम भील इन दिनों जोधपुर में पाक विस्थापितों की कॉलोनी में रह रहे हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता तो हाल ही में मिल गई है, लेकिन सरकारी लाभ से अभी भी वंचित हैं।

प्रेम भील बताते हैं कि जनवरी 2020 में ही भारतीय नागरिकता मिली है, लेकिन राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कुछ भी आईडी प्रूफ नहीं बना है। इसके चलते परेशानी ही परेशानी है। काम धंधे बंद पड़े हैं। सरकार की तरफ से महीने में एक बार ही 10 और एक बार 5 किलो आटा आया और हम परिवार में 11 सदस्य हैं। वह जोधपुर में ही सिलाई की दुकान पर काम करते हैं। साथ ही में इनका भाई भी काम कर परिवार पालन में हाथ बंटाता है। लेकिन अब काम बंद होने से इनके सामने परिवार पालने के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं।11 लोगों के परिवार में औसत हर दिन आधा किलो आटा मिलने से क्या इनकी भूख मिट पाएगी? यह सवाल इनकी परेशानी बयां करने लिए काफ़ी है। वहीं, 5 महीने पहले पाकिस्तान के अमरकोट से परिवार के साथ जैसलमेर आईं सेजा देवी के परिवार में एक बेटा और दो बेटियों को मिलाकर कुल पांच लोग हैं। वे कहती हैं, "पहले 400-500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पर जाते थे यह (मनोहर लाल), लेकिन अब तो घर ही बैठे हैं। एक दफा सरकार ने पांच दिन पहले ही 5 किलो आटा, तेल, मसाला दिए थे। लेकिन अब कुछ राशन नहीं है अब, कहां से लें हम?"

क्या कर रही है सरकार?

राजस्थान कf सरकार 4 हज़ार पाकिस्तानी विस्थापितों को सहायता मुहैया कराने का दावा कर रही है। लेकिन कई परिवारों तक यह सहायता नहीं पहुंच पाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने ज़रूरतमंद पाक विस्थापितों को भी राशन एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई है। प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए थे।

उधर, 25 साल से पाकिस्तानी विस्थापितों के लिए कार्य कर रहे सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा कहते हैं, "यह परिवार बेहद परेशानी में हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समेत किसी भी सरकारी योजना में यह नहीं हैं आते हैं। रजिस्टर्ड दिहाड़ी मजदूरों में भी यह शामिल नहीं हैं।" सोढ़ा बताते हैं कि "2004 से अब तक पाकिस्तान से करीब 40 हजार शरणार्थी आए हैं। इनमें 95 प्रतिशत तक भील आदिवासी और दलित हैं। जो मेहनतकश मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार पालन कर रहे हैं।